I say this because the Tea Board even today has not promoted the cause of India Generic promotion of tea helps only the tea industry of the world in general. To say drink tea is not the same thing as to say drink Indian tea.

Under the Foreign Exchane Regulations Act the foreign companies are required to sell 24 per cent of their shares to Indians. The hon'ble Minister knows very well that the Assam Tea Corporation as well as the Assam Tea Employees Cooperative Ltd. are both interested in the purchase of these shares as well as in the purchase of individual tea gardems. They are required to negotiate in London with these foreign companies whose local agents in India are already in possession of the management of these companies. I hope the Central Government will not remain neutral in this situation and just say that it is a matter between the parties. We do got want economic assistance from the Central Government. This Corporation and Assam Tea Co. Ltd. have not enough funds but certainly the Central Government can direct the Department of Economic Affairs as well as the Ministry of Commerce to help the public sector and the workers' organisation to get precedence over the local agents and the private companies in the matter of purchase of foreign shares.

Sir, I will take only one minute more. All the tea companies in Assam are registered outside Assam. This has got all its remifications and the State of Assam loses revenue and other facilities. Government should not stand neutral but see that their registered offices as well as the head offices of these companies are located or shifted to Assam.

Lastly, Sir, the hon'ble Minister has imposed an export duty on tea to discourage exports. This is not fair to the tea industry and the workers of tea industry in Assam. In other industries export incentives are given to encourage exports. We may not be given export incentives but not export duty should be imposed. Whatever money could be saved by a company from exports should rightly go to the workers who are one of the lowest paid amongst the working class of India.

MR. CHAIRMAN : The Minister.

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, several vital issues have been raised by the hon'ble Members during the debate. Several misapprehensions have also been expressed. I would like to take the House into confidence abont the state of affairs. For this purpose, naturally I required some time. There are hardly five minutes left before the House takes up Half-an-Hour discussion. It will not be possible for me to do justice in five minutes.

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhawnagar) : Sir, some Members on this side should also be given chance to speak. The hon. Minister can reply tomorrow.

MR. CHAIRMAN : The discussion will continue tomorrow.

17·30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

FERTILIZER FACTORY PROPOSED TO BE SET UP IN KORBA

MR. CHAIRMAN : We will now take up half-an-hour discussion regarding fertilizer factory proposed to be set up in Korba.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): सभापति महोदय, कोरबा में रासायनिक उर्वरक कारखाना जिसका प्रारम्भिक काफी कार्य पूर्ण हो चुका था उसके बारे में फिर से विचार करते हुए इस प्रकार की कार्यवाही करना कि इस कारखाने का काम शिथिल कर दिया जाये और रामगुंडम के कारखाने को प्राथमिकता दी जाये तथा जिस आधार पर निर्णय लिया गया वह वास्तव में मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के साथ अन्याय है जिस की एक तिहाई जनसंख्या आदिवासियों और पिछड़ी जातियों की है तथा पिछड़े इलाके में ही जिस कारखाने का निर्माण चल रहा हो। कार्य बन्द हो जाये यह कभी भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन के आधार पर तथा, इस आधार को मान कर भी कि इससे पिछड़े इलाके की उन्नति होगी, राज्य का औद्योगिक पिछड़ापन भी दूर होगा इस कारखाने को प्रारम्भ करने के दो, दो तीन तीन बार विचार करने के बाद, अर्थात् 1963 और 1965 में और 1969 में फिर तीसरी बार विचार हुआ और योजना आयोग की स्वीकृति के बाद इस कारखाने का निर्माण कार्य प्रारम्भ

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडे]

किया गया। किन्तु इस कारखाने का काम प्रायः बन्द कर देना यह हम सब के लिय अत्यन्त दुख की बात है और चिन्ता का विषय भी है। केवल यह प्रदेश का विषय नहीं है, आज देश भर में रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ती जा रही है और उसके आधार पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सिंदरी का कारखाना बिगड़ा हुआ है, उसका उत्पादन दिन प्रति दिन घट रहा है, बुड़ा हो गया है। इसी प्रकार से गोरखपुर कारखाने के बारे में भी है, लगातार बिजली की शिकायतों के कारण या बिजली समय पर न मिलने के कारण उसका उत्पादन भी काफी घटा है। ऐसी ही स्थिति अन्य कुछ कारखानों की है और यदि फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के लाभ के आंकड़े उठाकर के देख जायें तो वह हानि के आंकड़ों में परिवर्तित हो गए हैं। एफ0 सी0 आई0 लगातार घाटे में चल रहा है और घाटे की राशि 15 करोड़ से बढ़ कर 30 करोड़ तक पहुंच गई है। ऐसी दशा में हमारे जो पिछले कारखाने हैं उनकी उत्पादन क्षमता गिरी है और ठीक से उत्पादन नहीं हो रहा है, नया कारखाना सामने आवे इस दृष्टि से भी इस कारखाने की स्थिति बहुत अच्छी है। और चूंकि इस कारखाने के लिये भूमि ली जा चुकी थी, रेलवे साइडिंग भी वहां पर तैयार की जा चुकी थीं, उसका कंस्ट्रेक्शन प्रायः पूरा हो गया था, बिजली का 100 मेगावाट का एक फेज पूरा हो गया था और दूसरे फेज का कार्य प्रारम्भ हो गया था, पानी काफी है, कोयला भी काफ़ी है, शायद रामगुंडम और तालचेर में उतनी मात्रा में और उस क्वालिटी का कोयला उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन केवल राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक दुर्भाववश केवल मध्य प्रदेश की उपेक्षा करने की दृष्टि से इस प्रकार का निर्णय पिछली सरकार ने लिया है इस का मुझे दुख है। क्योंकि एक प्रकार से प्रदेश के साथ इस प्रकार का निर्णय कर के इस स्थिति को पहुंचाया गया है। यदि एक नये कारखाने का निर्माण पूरा होता तो देश की रासायनिक खाद की आवश्यकता की पूर्ति होती ?

जैसा मैंने कहा इस कारखाने के ऊपर लगभग 24 करोड़ रु० खर्च हो चुका है। रामगुंडम तालचेर या हल्दिया जैसे कारखाने देश के अन्य भाग में खुले मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उससे देश की सम्पत्ति की वृद्धि ही होती है और हमारी कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। सरकार इस दिशा में काम करें।

मैं कुछ अंश इंडियन फर्टिलाइजर स्टेटिक्स वर्ष 1975-76 से उद्धृत कर रहा हूं :

"During the year 1971 five contracts with various foreign contractors for the supply of equipment, know-how, design and spares, etc. were entered.. 1975 in April construction of township quarters was started. In May civil works for NPK Prilling Tower and Phospheric Acid Plant and prilling work in Urea plant completed. In June civil works of Urea prilling tower and Ammonia plant was started. In November Civil work of selos was started and pilling work in soda ash and bagging plant was completed."

यह सारे का सारा काम अगस्त में जाकर पूरा हुआ। वह जो सन् 1970 में काम प्रारम्भ हुआ वह 1975 में आकर पूरा हुआ।

लेकिन कोरबा के बारे में क्या हुआ ? इसका कार्य पूरी तैयारी से प्रारम्भ हुआ था तथा विचार विमर्श के बाद हुआ था। मेरे पास जो फर्टिलाइजर स्टेटिक्स रिपोर्ट वर्ष 1975-76 की है। उसके कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

"In September the feasibility report was received..... On 14th June, 1975,

project office shifted to Korba from Bilaspur. On 3rd September, the first major indigenous consignment consisting of one electric motors from M/s MGEF Calcutta was received. On 19th December, the first consignment from M/s. Techno Expert of Czechoslovakia for ASU and LNW plants was received."

बाहर के विदेशों से हमने जो सौदा किया, कंट्रेक्ट किया, उसके हिसाब से जो मशीनरी आई, उसकी सुरक्षा का साधन भी नहीं है। वह मशीनरी खराब हो रही है। कुछ मशीनों की 5 की या 7 बरस की गारन्टी होती है, लेकिन वह गारन्टी पीरियड भी अब समाप्त हो रहा है। या हो जायेगा। ऐसी आशा में इस कारखाने के काम को शिथिल करना या उसको ढीला करना भी ठीक नहीं कहा जा सकता।

मैं अपने माननीय मंत्री से आज की इस चर्चा के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इस कारखाने के बारे में फिर से विचार करते हुए जो इसका काम धीमा हो गया है, उसको जल्दी-से-जल्दी तेज गति से पूरा करने का प्रयत्न करें। जिससे कि यह कारखाना अपना उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ कर सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन यह प्रश्न उठाया गया था, माननीय मंत्री उस दिन यहां नहीं थे, उस दिन ला मिनिस्टर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था कि कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने तीनों तीन अलग-अलग राज्यों के थे। उन्होंने जो उत्तर दिया था वह मैं पढ़कर सुनाता हूं—

> "ऐसी कोई वजह नहीं थी कि मध्यप्रदेश से कोई शिकायत थी, इसलिए मध्यप्रदेश वाला बन्द कर दिया गया और आंध्र प्रदेश व उड़ीसा वाले चलाये गये। यह फैसला लेना था, इसलिये लिया गया।"

मेरा विश्वास है कि माननीय सभापति महोदय न्याय करेंगे कि जब कोई फैसला लेना था तो कोरबा के बारे में क्यों नहीं लिया गया ? केवल रामगुंडम के बारे में फैसला क्यों लिया गया ? यह फैसला कोरबा के लिये भी लिया जा सकता था। अथवा मैं जानना चाहूंगा कि फैसला लेने से पहले किन-किन तथ्यों को सामने रखा गया या उसका आधार क्या था ?

उनका दूसरा यह विचार था कि कोल-बेस्ड टैक्नोलाजी ठीक नहीं है, इसको डाइवर्ट कर के नेप्था बेस पर लाना चाहते है या और कोई दूसरी विधि अपनाना चाहते है। लेकिन आज कोल-बेस्ड कारखाने जर्मनी या दूसरे कई देशों में बड़ी सफलता से चल रहे है। उनके बारे में कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाये कि कोल बेस्ड कारखाने ठीक नहीं थे तो जब इन तीन कारखानों के निर्माण का प्रश्न पैदा हुआ, उस समय क्यों नहीं विचार किया गया ? इस टैक्नालाजी को उस समय क्यों ठीक माना गया ? करोड़ों रुपये व्यय करने के बाद में फिर से रिव्यू कर के जो विचार किया गया है, मैं समझता हूं कि इसके पीछे किन्हीं अधिकारियों और उस समय की सरकार में बैठे हुए मंत्रियों द्वारा जानबूझकर इस बारे में उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने का फैसला लिया गया जिसका उस समय की मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी पूरी तरह विरोध नहीं किया।

आगे मैंने कहा कि माननीय मंत्री उस दिन थे नहीं, विधि मंत्री ने उस समय उत्तर दिया था। मैं समझता हुं कि शायद उनको पूरी जानकारी न रही हो, लेकिन स्वयं उन्होंने कहा कि यह देखने के बाद कि कोल बेस्ड प्लान्ट कहां तक सक्सेसफुल होगा, उसके बाद तय किया जायेगा कि दूसरे कारखानों को बनाया जायेगा या नहीं ? किंतु ऐसा देखने या फिर से कोई विचार करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि पूरी जानकारी के बाद ही फैसला किया गया था।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडय]

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक हमारे खाद के निर्माण का प्रश्न है, इस समय देश में जहां अन्यान्य रासायनिक खादों की आवश्यकता है, वहां यूरिया का उत्पादन बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । इसी को लक्ष्य में रखकर कोरबा में भी रासायनिक उर्वरक कारखाने का निर्माण प्रारम्भ किया गया था क्योंकि 4.95 लाख टन वार्षिक क्षमता इस कारखाने की निश्चित की गई थी और इस प्रकार यूरिया की कमी जो आज बनी हुई है वह पूरी होती क्योंकि आवश्यकतानुसार यूरिया का उत्पादन नहीं हो रहा है ।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि पानी, बिजली, सड़क, जमीन इतना ही नहीं ट्रेनीज तैयार हो चुके थे और शिल्प का प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षक तैयार हो गये थे । कुछ दिन तक प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे ही बैठे रहे कि आगे काम होगा लेकिन जब काम स्लोडाउन किया गया तो उन प्रशिक्षणार्थियों को या प्रशिक्षितों को बाहर भेज दिया गया और उस प्रशिक्षण केन्द्र को जुलाई, 1975 में बन्द कर दिया गया और कहा गया कि भारत सरकार की ओर से धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है ।

जब योजना आयोग ने इस कारखाने की स्थापना को अपनी स्वीकृति दे दी थी, जब मध्य प्रदेश के विकास के लिए इस की बहुत आवश्यकता है और जब दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स की राय और नो-हाऊ ले कर इस कारखाने का निर्माण प्रारम्भ किया गया, तब बीच में ही इस काम को बन्द कर दिया गया जिससे खाद के उत्पादन और कृषि की उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ेगा । साथ ही यह मध्य प्रदेश की घोर उपेक्षा का स्पष्ट प्रमाण है ।

जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने इस कारखाने की आधारशिला रखी, तो मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसा लगा था कि अब यह कारखाना बहुत जल्दी बनने वाला है, और इस से हमारे पूरे प्रदेश तथा विशेषकर प्रदेश के छत्तीसगढ़ और महाकौशल जैसे पिछड़े हुए इलाकों का विकास होगा । पिछली सरकार ने शायद इस कारखाने के काम को किसी राजनैतिक कारण से रोक दिया । मैं उस के बारे में कुछ अधिक नहीं कह सकता हूं । किन्तु ऐसा हुआ अवश्य है । अतः मेरा निवेदन है कि जब इस कारखाने का काम प्रारम्भ हो चुका है, सभी कुछ वहां मौजूद है, तो इस बारे में पुनर्विचार कर के इसके काम को तेज गति से चलाया जाये, इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये, ताकि यह कारखाना उर्वरक का उत्पादन कर के मध्य प्रदेश तथा देश की उन्नति में भागीदार बने ।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore) : Sir, my friend Dr. Pandeya has ably presented the case of Korba and that it should be in Madhya Pradesh and that the construction work should be started.

I would like to ask the hon. Minister one important matter. Yesterday while replying to the debate on Oil and Natural Gas (Amendment) Bill, the Minister rightly had pointed out that it is not wise for our country to exhaust the oil resources that we have. The plant at Korba is a coal-based plant.

In our country, the technology which we are intending to use is oil based technology, and if we continue with that, it will naturally exhaust our oil resources, the much-needed oil resources, the scarce oil resources. If we import oil, that will make our nation indebted so much. India is one of the countries having enormous coal resources. We can even export. So, considering this aspect of the matter, I think the Government can consider rather positively in taking a decision in regard to coal-based technology fertiliser plants.

I would urge upon the Minister to reconsider the decision not only from the point of view that Madhya Pradesh is backward and that we have already spent Rs. 20 crores and the former Prime Minister has laid the foundation but considering the future interest of th

country. I hope that the Minister will assure the House that he will go in for coal-based technology in fertiliser production and that a decision on Korba will be taken very soon so that the coal-based production there in that fertiliser plant will help our nation. This is my submission.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कोरबा का जो कारखाना लगने वाला था यह कारखाना लगाने के लिए सर्वे कब हुआ था और इसको अनुमति कब मिली? क्या यह बात सही है कि इसकी अनुमति मिलने के बाद और सब प्रकार का सर्वे होने के बाद यहां 24 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका ? क्या सरकार इस उद्योग को और जगह ले जा कर 24 करोड़ रुपया बर्बाद करना चाहती है ? यदि नहीं तो इसे पूरा लगाने तक कितना खर्चा करने का विचार रखती है और कब तक पुनः इसको चालू कर दिया जायेगा ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Dr. Pandeya has very ably presented the case of Korba and we all support his stand. Madhya Pradesh deserves a coal-based fertilizer factory. It is a backward State and there are lot of coal reserves there. But it is indeed unfortunate that so far no positive step has been taken in that direction. I am reminded of 1974 when Shrimati Indira Gandhi visited Orissa for election propaganda, she inaugurated another fertiliser plant at Paradip. The minister may enlighten us as to what action has been taken about that ..

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS SHRI H.N. BAHUGUNA : What is the connection between the two ?

SHRI S. KUNDU : They are interconnected.....

SHRI H.N. BAHUGUNA : The same person laid the foundation stones of b oth !

SHRI S. KUNDU : Foundation stones were laid for many other fertiliser plants also. It was all meant to throw dust in the eyes of the people. It was a political gimmick to food the innocent and poor people. If the minister is not interested in doing something qucikly, at least in an organised manner, he should try to uproot the foundation stones wherever they have been laid with political consideration by Mrs. Inidra Gandhi.

This is very much linked with Paradip fertilizer factory based on coal. When we are thinking of export of coal in large quantities and about using coal and naphtha to make fertilizer, there cannot be a better location than Paradip. Technical studies and feasibility reports show that Paradip is a very suitable place. Therefore, Madam Gandhi was prompted to lay the foundation stone but with any sincere desire to actually work it. Mr. Bahuguna is a dynamic minister and I hope he will see that the injustice done to Orissa will be undone.

Another question connected with this is the production of oil from coal. We have a huge reserve 2000 million tonnes of coal. I do not know what has happened to the Chakravarti Committee report on this subject. Now the policy of the government is to switch over from oil to coal. For some time the government was swayed by certain misgivings that production of oil from coal would not be profitable. But I am told that in South Africa such a factory exists since 1955 and is also running profitably. Since we have such a large reserve of coal and since there is acute shortage of oil, will the minister kindly enlighten us to what he is going to do about this matter of producing oil from coal ?

SHRI H.N. BAHUGUNA: I am beholden to Dr Pandeya who has raised this question. I want to point out certain things.

Firstly, Korba was conceived, not in 1968 but in 1960, There are other also who have spoken; and I don't want to speak in a language which people will not understand. Repetition is a dangerous thing. I want to be correct and precise in this, so that I do not go wroing. It is actually ture that it was in 1960 that this particular project was conceived for the first time. It is also true that the project was cleared, after many vicissitudes, in the year 1972; and formal Cabinet sanction for the total project was accorded. It is also true that the foundation-stone was laid by the outgoing Prime Minister. It is also true that a large amount of money has been invested; and all arrangements have been made: e.g. process know-how form Germany, some other type of know-how from Italy etc. All have been entered into and the agreements are there. It is also true that Korba hasa very rich deposits of coal and is ideally suited for a coal-based plants. But unfortunately and unluckily for Korba,

[Shri H.N. Bahuguna]

1968 appeared to be a bad year. In 1968 suddenly it was suggested that naphtha should replace the feed-stock: and under the new philosophy, poor Korba started getting left aside; but ultimately in 1972 it came again on rails. What happened is that all types of reasons were advanced in the Ministry that Ramagundam will be a better place, because it was the centre of consumption, that there was better consumption in Andhra than in Madhya Pradesh because poor Madhya Pradesh did not have irrigation facilities, and so it is not the consuming centre; and as such we should first go to the consuming centre. Distortions started on this argument. I am not opposed to Ramagundam. To me, Ramagundam is as dear as Talcher or Paradip or any other place. Ultimately, the result was that Ramagundam and Talcher were selected.

Initially it was naphtha that diverted us to coal: later when naphtha became very costly in 1973 and oil crisis was there and prices went up, we came back to coal. When we came back to coal, it was thought that we should go back to the consuming centre, so that there is a marketing possibility. That left Korba again high and dry. Since then Korba was commonly accepted and government orders were issue. It was way back in 1972 that all these thing were done. I have not computed in terms of money; but I can say that the commitment made about Korba was rather large. If I may say so, the physical progress made is on these lines: *Total construction*—water supply has been done; boundary wall has been made; land has been acquired; factory area has been done: factory roads to the extent of the initial requirement has been completed; buildings have come: railway sliding has come. This siding will now be used for bringing in heavy consignments of things from the Vizag port. *Kutcha* drain has been made: and items like fire extinguisher, silica jar and wood preservatives have been completed. Equipments for ACW and NLW plants have started arriving. Total equipment received upto December 1976 comes to 3940 tonnes; and about 910.5 tonnes of equipment are in transit. *Contracts entered into:* Licences of know-how for grassification with Germany—Rs. 67 lakhs—already entered into. Know-how for ammonia synthesis with Technimont of Italy Rs. 43 lakhs; design know-how with Messrs. Techno Exports, Czechoslovakia—Rs. 752 lakhs: raw material with STC and Sukarp Rs. 165 lakhs; and total foreign currency commited—Rs. 1097 lakhs. Equipments ordered from Technoexport, Czechoslovakia, and other business concerns account for about Rs. 10 crores. All this is true. But, unfortunately, what happens was, in between there was shortage of money. Now where the axe falls? The axe was made to fall in 1975 on Korba. It was said that Korba must be slowed down. In the motion pictures you see slow motion. The whole thing is running very fast but you are shown it in slow motion. A foot ball match, though it is going on very very quick, is shown in slow motion. In the same way, Korba became so slow. Korba has not been dealt with correctly. But this distortion is not within my hands to make it return back to normal to its correct place at once by removing the distortion, so far as Korba is concerned. All I can assure the House is that it will be our endeavour to see how far and to what extent we can put Korba back on the rails.

My hon. friend has raised some other question. Since it was not connected with this, I do not have that information except.....

एक माननीय सदस्य : अवधि निर्धारित कर दीजिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस में मेरी कठिनाई है—यह सन् 1960 से लेकर अब तक 17 वर्ष का बीमार है । 17 वर्ष के बीमार की नाड़ी, नब्ज देख रहा हूं, कोई रास्ता जीवित करने का निकल आये—ऐसा सोच रहा हूं ।

All I can assure the House is that Korba will come on steam soon. We will see that it comes on steam soon. But the point is only when and how soon it will start. Now we are told that by the middle of 1979 it would be in steam.

श्री मदन लाल शुक्ल (जंजगीर): मैं स्वयं आठ रोज पहले वहां देख कर आया हूं, सब मशीनें खराब हो जायेंगी, पानी में पड़ी हुई है ।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : आप जो कह रहे है, मैंने उस को मना नहीं किया है, ऐसा हो रहा होगा । वहां जो सड़क बनी थी, वह खराब हो रही होगी, इमारत भी खराब हो रही होगी । मकान बना दिया जाय और कोई उसमें रहे नहीं, तो वह भी खराब हो जाता है ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा): आप ने कहा है कि 1979 के मध्य तक हो जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस की सलाह मुझे सब तरफ़ से मिली है । मैं अपनी तरफ़ से सिर्फ इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं--जितना दर्द, जितनी पीड़ा आप को है, उस पीड़ा को अपने साथ हमेशा रख कर इस प्रश्न को सहानुभूति-पूर्वक देखूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा, इस को कराने की कोशिश करूंगा । कठिनाई ज़रूर है, पैसे की भी कठिनाई है । यह भी सोचा गया था कि कुछ इस की टैकनालाजी को बदल दिया जाय, लेकिन वह भी अब सम्भव नहीं है, क्योंकि जो इक्विपमेण्ट और प्लांट लिया गया है, उस के आधार पर ही कोल गैस बनाना है और फिर उस से फर्टिलाइज़र बनाना है । इसलिए इस काम में थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : नेपथा दिन-प्रति-दिन महंगा हो रहा है और फिर से यह विचार चल पड़ा है कि कोल बेस्ड उर्वरक कारखाना ही लगाया जाना लाभ प्रद होगा । अतः आप कोरबा के कारखाने का काम शीघ्र प्रारम्भ करें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नेपथा तो सम्भव नहीं है । कोयले के आधार पर ही सब काम हुआ है । पांच मुल्कों में इस की शुरुआत हुई थी । कोरबा पहले शुरू हुआ, लेकिन रामगुण्डम और तालचेर ने लूट लिया, अब यह किस्मत की बात है.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप लुट गये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कभी-कभी ऐसा होता है, कछवाय जी जानते है--आप गणपूर्ति करते रहे, मिनिस्टर हम लोग हो गये ।

तो, मान्यवर, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि--डा० पाण्डे जानते है, उन का मेरे साथ पहले भी सम्पर्क हो चुका हैं, जब मैं संचार मंत्री था और आज तो वे मेरे बहुत ही करीब है--मेरे दिल में, पिछड़े क्षत्रों, पिछड़े इलाकों के सम्बन्ध में ज़रूर ध्यान रहता है । मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि इस को पूरे तौर से करूंगा ।

I may assure my hon. friend, Shri Chandrappan, also that it is our keen desire to see that this inconvenient episode, which started somewherein 1960 and remained off rails till 1977, is something which is, of course, a very unfortunate, if not disgraceful situation in which we are, and we will try to get out of it soon. It is my endeavour to do it.

So far as the protection of plant and machinery is concerned, I can tell you that I have put the FCI on the alert on it to see that the plant, machinery and other things are not left open to the vagaries of the weather.

In any case, this is the difficulty, this is the position, which is hardly reasonable, but I have inherited many things which are not reasonable and this is one of the unreasonable things which we have inherited. You have to bear with us for a while and see how we can rescue this out of disaster.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 27, 1977/ Sravana 5, 1899 (Saka).

GMGIPND—M..1928 L.S...12-9-77—998